HRA En USIUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUELISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

No. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2006

सं. 8-13/2004-एफ पी.—भारत सरकार ने वनों और वन्यजीव क्षेत्र की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए भारत सरकार के संकल्प संख्या का. अा. 143(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2003, का. आ. 34(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2005 और सं. 8-13/2004-एफ पी, दिनांक 22 अगस्त, 2005 के तहत भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 2006 तक की अविध के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया है। आयोग को सौंप गए कार्यों को पूरा करने के लिए इस आयोग की निर्धारित अविध को और 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

जी. के. प्रसाद, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS RESOLUTION

New Delhi, the 30th January, 2006

No. 8-13/2004-FP.—To review the working of the Forests and Wildlife Sector, the Government of India has constituted a National Forest Commission under the Chairmanship of Justice B. N. Kirpal, Ex-Chief Justice of India vide Government of India Resolution No. S. O. 143(E), dated 7th February, 2003 and extended vide S.O. 34(E), dated 6th January, 2005 upto 6th August, 2005 and upto 6th February, 2006 vide Government of India Notification No. 863 [S.O. 1145(E)] dated 7th August, 2005. It has been decided to further extend the time prescribed for the Commission to complete its assigned task upto 31st March, 2006.

G. K. PRASAD, Addl. Director General of Forests